www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 233 | जौनपुर सोमवार, 13 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी, को 1311 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

लखीमपुर खीरी , (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वह दो कार्यक्रमों में शामिल होकर जिलेवासियों को 1311 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पहला कार्यक्रम पलियाकलां तहसील के थारू क्षेत्र चंदनचौकी में है। वहां पूर्वाह्न करीब 11रू30 बजे पहुंचकर एक घंटे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें थारू परिवारों एवं पूर्वी पाकिस्तान से आकर यहां बसे हिंदू परिवारों को भूमि पर मालिकाना अधिकार के पत्र प्रदान करेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी देंगे। इस तरह का आयोजन मोहम्मदी के मियांपुर में किया गया है। यहां मुख्यमंत्री दोपहर 1रू10 बजे पहुंचेंगे। दोनों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 1311 करोड़ रुपये से जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए 538 परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 356 करोड़ रुपये की 345 परियोजनाओं का लोकार्पण और 955 करोड़ रुपये की 193 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद के चंदनचौकी और मियांपुर में पहुंचेंगे। जहां विस्थापित परिवारों के साथ जनपद वासियों को बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दो

अलग–अलग स्थानों पर होने से सरकारी अमले में आपाधापी बची है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन दो भागों में बांटा गया है। डीएम, एसपी सहित अन्य अफसर चंदनचौकी में कमान संभालेंगे, जबकि मियांपुर में कमिश्नर, सीडीओ, एडीएम सहित अन्य अफसर रहेंगे। प्रशासन का दावा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सबसे पहले पलिया के चंदन चौकी पहुंचेंगे, जहां थारू परिवारों एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां आए आवासित परिवारों को भौमिक अधिकार प्रदान करेंगे। योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण देंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाभी देंगे। निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इस दौरान बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत 'ओडीओपी' योजना के तहत निर्मित हैट पहनाकर किया जाएगा। इसके बाद सीएम मोहम्मदी के मियांपुर पहुंचेंगे। जहां विभाजन के समय विस्थापित परिवारों को भौमिक अधिकार देंगे।

ज्योतिबा फुले जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई नेताओं ने शनिवार को संसद परिसर में ज्योतिराव फुले की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई सांसदों ने भी समाज सुधारक को श्रद्धांजलि दी। ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए अहम योगदान दिया। उन्होंने समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि ज्योतिराव फुले ने अपना जीवन वंचित समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेशी समाज की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फुले के प्रयासों ने एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की नींव रखी। राहुल गांधी ने उन्हें सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाने वाला महान सुधारक बताया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बताया। नेताओं ने कहा कि ज्योतिबा फुले के विचार और आदर्श आज भी समाज को समानता, शिक्षा और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

संक्षिप्त खबरें

सीएआरआई बेंगलुरू को अंतरराष्ट्रीय मान्यता, आयुष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली, (एजेंसी)।केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), बेंगलुरु ने जैव रसायन एवं रुधिरविज्ञान क्षेत्र में आईएसओ 15189रू2022 मान्यता प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि इसे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) का पहला संस्थान बनाती है जिसे यह वैश्विक मान्यता मिली है। संस्थान ने प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक परीक्षणों के साथ 50 मापदंडों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। एनएबीएल प्रमाणन के बाद प्रयोगशाला ने और सख्त आईएसओ 15189रू2022 मानकों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि यह वैश्विक मान्यता सटीक निदान सुनिश्चित करती है और आयुष को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के मानक के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने इसे प्रमाण–आधारित आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए एक मजबूत कदम बताया। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आईएसओ 15189रू2022 मान्यता प्रमाण–आधारित अभ्यास और अनुसंधान को और मजबूत करती है। इससे आयुर्वेदिक उपचारों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता बढ़ेगी।

समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने पर फोकस, राजीव रंजन सिंह ने की अहम बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में समुद्री खाद्य निर्यातकों की बैठक 2026 की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और निर्यात को मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में मंत्री ने कहा कि भारत मूल्य–वर्धित समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाएगा और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) तथा खुले समुद्र की क्षमता का बेहतर उपयोग करेगा। साथ ही निर्यातकों के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया गया। मंत्री ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से निर्यातकों के समर्थन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को मजबूत करने का आग्रह किया, ताकि अनुपालन, प्रतिस्पर्धा और निर्यात तैयारी को बढ़ाया जा सके। बैठक में हितधारकों ने कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें कैच सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल बनाना, अंडमान– निकोबार में समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुमति सुविधा, और उच्च गुणवत्ता वाले फिश फीड के वैज्ञानिक विकास की जरूरत शामिल रही। इसके अलावा टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएं, उच्च लागत, कोल्ड चेन की कमी और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहित कई संस्थानों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तीन दिवसीय लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह, 'सांसद खेल महाकुंभ' का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे 'सांसद खेल महाकुंभ' का शुभारंभ करेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह का विमान दोपहर 3:20 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरेगा। लंबे

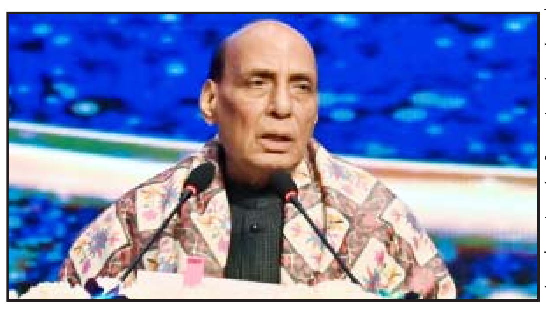

समय बाद हो रहे इस दौरे के दौरान उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रखा गया है। शाम 4:30 बजे वे गोमती नगर स्थित टंकी वाला पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5रू45 बजे कैंट क्षेत्र के सूर्य ऑडिटोरियम में युद्ध नायकों और वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। शाम 6रू35 बजे रक्षा मंत्री स्मृतिका वॉर मेमोरियल और लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे करीब 7रू15 बजे कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पहुंचेंगे। इससे पहले दिन में राजनाथ सिंह और मोहन यादव मध्य प्रदेश के रायसेन में 'उन्नत कृषि महोत्सव' का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है, जिसकी पहल शिवराज सिंह चौहान ने की है। 'कृषि महाकुंभ' नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को 'लैब टू फील्ड' और 'सीड टू मार्केट' तक की पूरी जानकारी देना है। महोत्सव में आधुनिक खेती की तकनीक, प्रशिक्षण, लाइव डेमो और बाजार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

भाजपा को सत्ता में लाओ, हम सिंडिकेट चलाने वालों को उल्टा लटका देंगे– अमित शाह

कोलकाता, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में अवैध रूप से रहने वालों को अगर कोई हटा सकता है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी अवैध लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाओ, हम सिंडिकेट चलाने वालों को उल्टा लटका देंगे। केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी की तुलना हीरक की रानी से करते हुए कहा कि इस रानी को 23

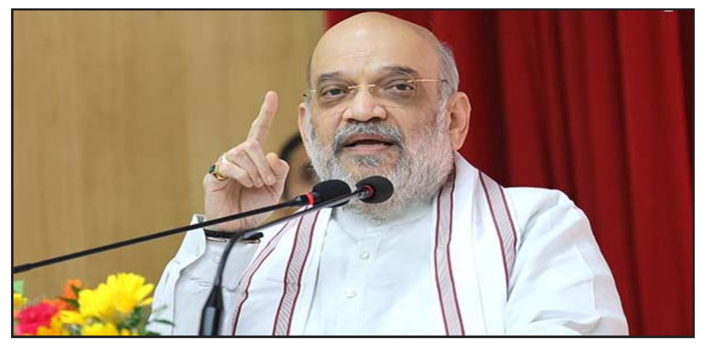

तारीख को हटाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से ओडिशा और झारखंड में आलू की सप्लाई बंद कर दी गई है। अगर भाजपा सत्ता में आई, तो यह सप्लाई फिर से शुरू होगी। ममता बनर्जी के इस फैसले के कारण 20 रुपए का आलू 2 रुपए में बिक रहा है। अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा बंगाल के विकास के लिए भेजे गए फंड को टीएमसी के सिंडिकेट ने हड़प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर टीएमसी को हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। आदिवासी समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में संथाल समाज को कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन भाजपा सरकार में इसी समुदाय की एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब राष्ट्रपति बंगाल आईं, तो उनका अपमान किया गया। अमित शाह ने घोषणा की कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य का मुख्यमंत्री एक बंगाली नेता ही होगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक समान कानून होगा। ममता बनर्जी के उस बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने लड़कियों को शाम 7 बजे के बाद बाहर न निकलने की सलाह दी थी।

महात्म फुले के सपनों को साकार करेगा नारी शक्ति वंदन बिल : नितिन नबीन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 31 जनवरी, 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोकसभा में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों के अनुरूप है। नबीन के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम और तरुण चुघ भी नई दिल्ली में फुले को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद थे। महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय समाजसेवी, सुधारक और लेखक थे, जिनका जन्म 11 अप्रैल, 1827 को सतारा में हुआ था। उन्हें जाति व्यवस्था के उन्मूलन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और

शोषितों के सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि किसानों और निम्न जाति के लोगों को समान अधिकार मिल सकें। मीडिया से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि समाज सुधार में उनके योगदान के लिए देश आज भी उन्हें याद करता है। पहले बालिका विद्यालय की स्थापना से लेकर सती प्रथा के उन्मूलन में उनकी भूमिका तक, हमारा मानना घ्है कि यह आज भी प्रासंगिक है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने तक, प्रधानमंत्री मोदी ये सभी कार्य कर रहे हैं३ 33 प्रतिशत आरक्षण ज्योतिराव फुले के आदर्शों के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसमें कम से कम 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैंय प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ, सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से लगभग एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन विधेयक के मसौदे को पहले ही मंजूरी दे दी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रतिबद्ध आंध्र प्रदेश की सरकार, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया सुरक्षा और विकास का भरोसा

आंध्र प्रदेश (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछड़ा वर्ग (ठब्) के उत्थान को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उन्होंने दोहराया कि सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उनके समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केसाना शंकर राव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। नायडू ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उनके समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार के

सामने आबादी के अनुपात के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मुद्दा उठाएं। उन्होंने पिछड़े समुदायों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की भी मांग की। साथा ही स्थानीय निकायों में 34 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने, समर्पित बजट आवंटन के साथ ओबीसी उप–योजना शुरू करने और सरकारी विभागों में लंबित रिक्तियों को भरने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करेगी।

भारत–जीसीसी के बीच मजबूत आर्थिक रिश्तों पर जोर, पीयूष गोयल की अहम बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदैवी के साथ वर्चुअल बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान पीयूष गोयल ने क्षेत्र में घोषित युद्धविराम के कायम रहने की उम्मीद जताई और कहा कि इससे स्थायी

शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने दोहराया कि मतभेदों का समाधान केवल आपसी संवाद के माध्यम से ही संभव है। केंद्रीय मंत्री ने भारत और जीसीसी देशों के बीच मजबूत जन–संबंधों को आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्तों का आधार बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीसीसी क्षेत्रीय एकजुटता में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। पीयूष गोयल ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने और वैकल्पिक मार्गों की खोज के प्रयासों की सराहना की। दोनों पक्षों ने निर्बाध और सुचारू व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वैश्विक आपूर्ति प्रणाली मजबूत बनी रहे। बैठक में सहयोग और पारस्परिक समर्थन के साथ भारत–जीसीसी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई।

आबकारी परिसर में स्थित झाड़ी मे लगी भीषण आग, सीएफओ व एफएसओ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। सोमवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के आबकारी विभाग गोदाम परिसर में स्थित आबकारी गोदाम की झाड़ियां में अचानक अज्ञात कारण से भीषण आग लग गई। इससे पहले कि अग्निकांड से गोदाम में स्थित देसी शराब में आग पकड़ती कि उससे पहले घटना की सूचना पाते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे व अन्य अग्नि सम्मान कर्मियों के साथ मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। बताते चले सोमवार को दोपहर आबकारी विभाग मे स्थित झाड़ियों में अचानक आग लग गई। और देखते ही देखते यह आग पूरी तरह फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।इस मौके पर

दमकल की चार गाड़ियां लगी रही। बताते चले जहां पर यह अग्निकांड हुआ था वहां पर लॉडर्स डिस्टलरी लिमिटेड सीएलटू और रेडिको खैतान लिमिटेड का देशी शराब का गोदाम भी स्थित था।मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए 04 टेंडर अतिशीघ्र पहुंची एवं अथक परिश्रम करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया तथा आबकारी विभाग के गोदाम को सुरक्षित बचा लिया। आग बुझाने में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पाण्डेय,लीडिंग फायरमैन जयमूर्ति यादव,फायर सर्विस चालक मनोज कुमार सिंह,फायर सर्विस चालक राकेश मिश्रा,फायर सर्विस चालक रंगी लाल,फायरमैन दुर्गेश तिवारी, फायर मैन राघवेंद्र प्रताप सिंह,फायरमैन सलाउद्दीन,फायरमैन सूरज यादव,फायरमैन सिकंदर,फायरमैन सूर्य कुमार यादव,फायरमैन अमन शुक्ला,फायरमैन निशांत सिंह फायरमैन आलोक मिश्रा,फायरमैन दिनेश मिश्र,फायरमैन अतुल कुमार वर्मा,फायरमैन सुनील तिवारी व फायरमैन सुनील शुक्ला सहित अन्य अग्निशमन कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही।

संपादकीय

युद्ध से कोरोना जैसा संकट

मोदी ने संकटकाल में राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। मगर इसके लिए विपक्ष और देश को भरोसे में लेने का कोई इरादा उन्होंने नहीं जताया। ऐसे में उनका बयान कोई नई दिशा दिखाने में सफल हुआ, ये कहना कठिन है। प्रधानमंत्री की इस बात से सहज सहमत हुआ जा सकता है कि पश्चिम एशिया में युद्ध से भारत के सामने कोरोना महामारी जैसा संकट खड़ा हुआ है। उनकी ये बात भी सही है कि इस संकट का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। मगर उनकी ये बात उतनी ही आसानी से गले नहीं उतरती कि ये चुनौतियां अप्रत्याशित ढंग से सामने आईं। ना ही उनका ये कथन सहज स्वीकार्य है कि गुजरे एक दशक में उनकी सरकार ने जो तैयारियां कीं, वे इस वक्त काम आ रही हैं। हकीकत यह है कि रसोई गैस आपूर्ति में आई रुकावटों से देशवासी मुसीबत में फंसे हुए हैं, देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर उर्वरक का गंभीर संकट मंडरा रहा है, और भीषण महंगाई की आशंका हर रोज सघन होती जा रही है। बेशक, इस पूरी हालत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसकी व्यापार एवं विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं ने हालात ज्यादा मुश्किल बनाए हैं, यह भी जग–जाहिर है। अमेरिकी दबाव में रूस से रियायती दर पर तेल लेना बंद करना एक ऐसी ही प्राथमिकता थी। अब संकटकाल में जब अमेरिका ने रूसी तेल को प्रतिबंध मुक्त किया है, तो भारत को बाजार भाव पर वही तेल खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह पश्चिम एशिया में सबसे समान दूरी की नीति छोड़ने की महंगी कीमत अब चुकानी पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने संसद के मंच पर अपनी नीतियों के पक्ष में कोई दमदार दलील पेश नहीं की। बल्कि पश्चिम एशिया के बारे में एकमात्र नीतिगत बयान यह दिया कि होरमुज जलडमरूमध्य को बंद करना अस्वीकार्य है। मगर, इससे यह बात गायब रही कि ये रास्ता किसने बंद किया और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस संबंध में विपक्षी दलों ने अपनी अलग राय रखी है। लोकसभा में दिए बयान में मोदी ने संकटकाल में राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। मगर इसके लिए विपक्ष और पूरे देश को भरोसे में लेने का कोई इरादा उन्होंने नहीं जताया। ऐसे में युद्ध के 24वें दिन जाकर दिया गया उनका बयान कोई नई दिशा दिखाने और जन–विश्वास पैदा करने में सफल हुआ, यह शायद ही कहा जा सकता है।

जहां से हुआ था भारत पर कब्जा, ट्रेड रूट बंद करना था कारण

अभिनय

ईरान अब स्टेट ऑफ हॉर्मोस के मैनेजमेंट को नए स्तर पर ले जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनई की मौत के बाद देश में 40 दिनों का शोक था। 9 अप्रैल को 40 दिन पूरे हुए और इसी दिन नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का मैसेज टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ। उन्होंने यह साफ किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस का मैनेजमेंट अब नई तरह से होगा और यह बदलाव खुद ईरान करेगा। मुस्तफा खामेनई के इस मैसेज से पहले भी ईरान इस बात का संकेत दे चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस अब पहले जैसा नहीं होगा। नए स्टेटमेंट से यह और भी क्लियर हो चुका है कि ईरान अब कंट्रोल के साथ–साथ उसका मैनेजमेंट भी बहुत मजबूत करने वाला है। इसकी तैयारी में है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोस को लेकर और कड़े प्रतिबंध जारी कर सकता है। मोजतबा ने ईरान की जनता से एकजुट रहने और ऐसे मीडिया आउटलेट से दूर रहने की सलाह दी है जो अमेरिका या इजराइल को सपोर्ट करते दिखे। उन्होंने कहा, भले ही 40 दिनों का शोक पूरा हो गया है, लेकिन दुश्मन से बदला लेने का जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वह अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। ईरान अपने मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामिनई और अपने शहीदों का बदला लेने के लिए पक्का इरादा रखता है। ईरान अभी भी अपने साउथ के पड़ोसियों से एक सही रिएक्शन का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपना भाईचारा दिखा सके। साल 1498 वास्कोडि गामा अपने जहाजों के साथ भारत के तट पर पहुंचे। कालीकट जो आज केरल में कोजीकोट है। यह पहली बार था कि कोई यूरोपियन समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था। अफ्रीका केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए उस जमाने में भारत से आने वाले मसाले यूरोप में सोने जितने कीमती थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल यह सब चीजें भारत से अरब व्यापारियों के जरिए जमीनी रास्ते से पहले फारस की खाड़ी या लाल सागर तक जाती थी। फिर वहां से मिस्र और इटली के वेनिस शहर तक। वेनिस के व्यापारी इन मसालों को पूरे यूरोप में बेचते थे। इस पूरी सप्लाई चेन में अरब व्यापारी और वेनिस के सौदागर बिचोलिए थे और यह बिचोलिए इतना मुनाफा कमाते थे कि जब तक मसाले यूरोप पहुंचते उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती थी। वास्कोडिगामा की यात्रा ने पुर्तगाल की राजधानी लिसबन को एक आईडिया दिया। लिसबन को यह समझ आ गया कि अगर वह समुद्री रास्ते पर कंट्रोल कर ले तो बिचौलियों को काटकर सीधे मसालों का व्यापार किया जा सकता है। और इसके लिए उसे जमीन पर राज करने की जरूरत भी नहीं है। बस समुद्र के कुछ अहम ठिकानों पर कब्जा चाहिए था। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1505 में एक प्लान बनाया और इस प्लान में तीन जगहें थी। पहला अदन जो लाल सागर के मुहाने पर है ताकि मिस्र और अलेक्जेंड्रिया जाने वाले व्यापार को रोका जा सके। दूसरा था होर्मुज जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर है ताकि बैरूद और फारस जाने वाला रास्ता बंद हो और तीसरा मलक्का जो आज के मलेशिया में है ताकि चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कंट्रोल हो सके। तीनों जगह समुद्री रास्तों के चोक पॉइंट थी। मतलब ऐसे तंग रास्ते जहां से होकर गुजरे बिना कोई जहाज आगे नहीं जा सकता। इन तीनों पर कब्जा करो तो हिंद महासागर का पूरा व्यापार तुम्हारे हाथ में। और इन तीनों में सबसे अहम था होर्मुज। होर्मुज एक छोटा सा टापू है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। आज यह ईरान का हिस्सा है। लेकिन उस जमाने में यह एक अलग छोटी सी सल्तनत थी जिसका अपना राजा था। यह राजा सफाविद ईरान के शाह इस्माइल को टैक्स देता था। हॉर्मूस उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यापारिक ठिकानों में से एक था और एक फारसी कहावत थी कि अगर दुनिया एक अंगूठी है तो होर्मुज उसमें जड़ा हीरा है और इसकी वजह भी थी कि यहां से बहुत सारी चीजें गुजरती थी। भारत से आने वाले मसाले, कपड़े, इंडोनेशिया से आने वाली लौंग और जायफल, फारस से जाने वाला रेशम, बहरीन से आने वाली मोती और सबसे जरूरी अरब और फारस से भारत जाने वाले युद्ध के घोड़े। यह घोड़े वाला हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि इसका संबंध सीधे भारत से है। उस जमाने में भारत के दक्कन में कई सल्तनतें थी। बहमनी सल्तनत जो बाद में पांच छोटी सल्तनतों में बंट गई और विजयनगर साम्राज्य इन सबको लड़ाई के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे। भारत में जो देसी नस्ल के घोड़े मिलते थे, वह दक्कन की भीषण गर्मी में भारी भक्तबंद सिपाही को लेकर ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते थे। अरबी और फारसी घोड़े इस काम के लिए कहीं बेहतर थे। तो भारत के राजा भारी कीमत देकर अरब और फारस से घोड़े मंगाते थे। पुर्तगाली व्यापारी नूनीस ने लिखा है कि 16वीं सदी के पहले हिस्से में विजयनगर का राजा हर साल होर्मुज के रास्ते से करीब 13,000 घोड़े इंपोर्ट करता था। पुर्तगालियों ने हॉर्मूज पर सीधा राज नहीं किया। लोकल राजा अपनी जगह बना रहा लेकिन असली कंट्रोल पुर्तगालियों के पास था। राजा को टैक्स देना होता था। शुरू में

सालाना सोने के सिक्के दिए जाते थे। बाद में पुर्तगालियों ने पूरी कस्टम ड्यूटी ही अपने हाथ में ले ली और सबसे अहम चीज थी कार्तताज सिस्टम। कार्तताज एक तरह का लाइसेंस था या यूं कहें कि समुद्री पासपोर्ट। हिंद महासागर में कोई भी जहाज चलाना हो तो उसे पुर्तगालियों से यह कारतताज लेना पड़ता था। । पुर्तगालियों ने हॉर्मूस पर करीब 107 साल राज किया। लेकिन धीरे–धीरे उनकी पकड़ कमजोर होती गई। एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य ने में हॉर्मूस पर हमला किया। हालांकि वह हमला नाकाम रहा। दूसरी तरफ सफाविद ईरान के शाह अब्बास जो 1588 से 1629 तक सत्ता में रहे उन्होंने पुर्तगालियों से बहुत नाराजगी रखी। 1615 में बंदर आवास जो हॉर्मूस के सामने सामुद्रिक तट पर था वो भी ले लिया गया। लेकिन हॉर्मूस लेने के लिए शाह अब्बास को नेवी चाहिए थी और सफावेद ईरान के पास मजबूत नेवी नहीं थी। यही एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेज उस वक्त फारस के रेशम के व्यापार में दिलचस्पी रखते थे। होर्मुज सिर्फ मसालों का रास्ता नहीं था। यह भारत की सैन्य ताकत की सप्लाई लाइन भी थी। जो भी हॉर्मोस को कंट्रोल करेगा वो भारत जाने वाले घोड़ों को भी कंट्रोल कर सकता था। मसालों को भी, रेशम को भी और सोना चांदी के फ्लो को भी। पुर्तगालियों ने यह बात बहुत अच्छे से समझ ली थी और साल 1507 जुलाई का महीना आया। अफोंसो द अल्बुकरर्क नाम का एक पुर्तगाली जनरल छह जहाजों और 500 सिपाहियों के साथ हॉर्मूस की तरफ निकला। अल्बुकरर्क एक तजुर्बेकार फौजी था जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिमों के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे।

युद्धविराम और हाशिए पर धकेल दिया गया भारत

डॉ. मलय

मिश्रा यह युद्ध स्पष्ट रूप से नेतन्याहू की देन है और ट्रम्प इसके परिणामों के बारे में सोचे–समझे बिना ही इसमें फंस गए। अमेरिका के नाटो सहयोगियों द्वारा उनके हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने या अमेरिकी ठिकानों के उपयोग करने की अनुमति देने से इंकार करना अंतिम झटका साबित हुआ जिसने ट्रम्प को इस क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जलडमरूमध्य अभी भी ईरान के नियंत्रण में है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा मंगलवार 8 अप्रैल को घोषित दो सप्ताह का विराम एक राहत की बात है लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के पतन से चिह्नित नई भू–राजनीतिक गतिशीलता में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह अनिश्चित है कि युद्ध पूरी तरह से कब समाप्त होगा परन्तु यह निश्चित है कि क्षेत्र की संरचना फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध दूसरे महीने में भी आक्रामक और खतरनाक रूप ले चुका है। यह शायद दो दशकों में सबसे विनाशकारी संघर्ष है। इजरायल–अमेरिका और ईरान सैन्य शक्ति के नजरिये से एक असमान और विषम युद्ध लड़ रहे हैं जिसके उद्देश्य तेजी से बदलते रहे हैं और उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। इस विनाशकारी तबाही और नरसंहार में अब तक कई प्रवासी भारतीयों सहित 3000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विश्वविद्यालयों, परमाणु, बिजली और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध तेजी से बढ़ा है और क्षेत्रीय स्तर पर फैल गया है जिसके दूरगामी परिणाम खाड़ी क्षेत्र से परे हैं।इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को श्आतंकवाद का स्रोतश एवं हमास, हिजबुल्लाह, हूथी विद्रोहियों तथा इराक एवं सीरिया के मिलिशिया जैसे गैर–सरकारी संगठनों का संरक्षक बताते हुए श्अस्तित्वगत खतराश और श्विनाशकारीश कहा था। वेनेजुएला में अपने अभियान और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बेतुकी मांगें करने वाले अस्थिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा तैयार की गई युद्ध की योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया। ईस्लामी शासन ने बड़े पैमाने पर चले जनांदोलन और जनवरी में एक महीने तक चले दंगों द्वारा क्रूरतापूर्वक कुचल दिया, फिर भी इसने एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान की और सत्ता परिवर्तन आक्रमणकारियों का पहला घोषित युद्ध–लक्ष्य बन गया। युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, 40 शीर्ष सैन्य व सुरक्षा अधिकारियों और उनके परिवारों के करीबी सदस्यों की लक्षित हत्या कर दी गई। बंकर में जाने से इंकार करते हुए 86 वर्षीय अयातुल्ला ने सच्चे शिया इस्लामी परंपरा के अनुसार शहादत को गले लगाना उचित समझा। इसके तुरन्त बाद ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में चुने जाने वाले मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन ईरानी क्रांतिकारी गार्ड कोर और मौलवियों के मजबूत समर्थन से युद्ध प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान की जनता से विद्रोह करने तथा अपनी सरकार पर कब्जा करने का आह्वान करने वाली योजना बुरी तरह विफल हो गई। इसके विपरीत इन जघन्य हत्याओं ने जनता को एकजुट कर दिया और वे क्रांति के श्शत्रुओंश से लड़ने में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के लिए यह अस्तित्व का युद्ध थाय अपनी संप्रभुता पर हुए इस कपटपूर्ण, अवैध और पूरी तरह से अनुचित हमले से खुद को बचाना था। ईरान पिछले 20 वर्षों से ऐसी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की तैयारियां कर रहा था और पिछले जून में अमेरिका समर्थित इजरायल द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए क्रूर हमलों के 12 दिवसीय युद्ध के अनुभव से उसने कई सबक सीखे थे।ईरान की एकीकृत कमान प्रणाली एक विकेन्द्रीकृत कमान और नियंत्रण संरचना में बदल गई जिसमें सभी 30 प्रांतों ने अलग–अलग कमांडरों के अधीन अपनी–अपनी सेनाएं गठित कीं। ये कमांडर तेहरान स्थित केंद्रीय कमान में स्थित सर्वोच्च नेता के समग्र निर्देशन में स्वायत्त रूप से लड़ेंगे। इसके अलावा शीर्ष स्तर के समाप्त होने की स्थिति में सत्ता समूहों को कार्यभार संभालने के लिए तैयार किया गया था। दूसरे, फारस की खाड़ी के तट सहित पूरे देश में विस्तृत भूमिगत सुरंगों का निर्माण करके वे अपनी मिसाइल और ड्रोन उत्पादन क्षमता को बरकरार रख सके और समन्वित और आक्रामक तरीके से हमले कर सके। शुरुआत में वे दुश्मन के अवरोध ाक विमानों और वायु रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने के लिए अपनी पुरानी मिसाइलों का उपयोग करते थे जबकि अपनी नवीनतम तथा तकनीकी रूप से उन्नत मिसाइलों और ड्रोनों को बाद के उपयोग के लिए सुरक्षित रखते थे। चीन और रूस जैसी दो महाशक्तियों के स्पष्ट समर्थन से शक्तिशाली अमेरिका के खिलाफ ईरान 21वीं सदी का युद्ध लड़ रहा है। ईरान जानता है कि वह अमेरिका–इजरायल गठबंधन को हरा नहीं सकता लेकिन वह उन्हें और क्षेत्र में उनके सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वह दर्द और बलिदान सह सकता है, लेकिन बदले में दर्द भी पहुंचा सकता है और अंत तक लड़ सकता है।यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या यह युद्ध अमेरिकी कांग्रेस अथवा संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना शुरू हुआ था या राष्ट्रपति ट्रम्प ने नेतन्याहू के साथ पूरी तरह से गठबंधन द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में शुरू किया था जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल एवं ड्रोन उत्पादन क्षमता को नष्ट करना था। अमेरिका में शक्तिशाली यहूदी लॉबी ने इजरायल के लिए वाशिंगटन का पूर्ण समर्थन हासिल करने के लिए अथक प्रयास किए थे। युद्ध के दौरान भूगोल और ऊर्जा ईरान के सबसे बड़े हथियार रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) वैश्विक ऊर्जा की जीवनरेखा है जिससे होकर वैश्विक तेल और गैस का 20 प्रतिशत से अधि ाक परिवहन होता है। होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण के साथ इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजरायल के महत्वपूर्ण सैन्य, नागरिक व परमाणु लक्ष्यों पर सटीक हमले करके ईरान शक्ति का केंद्र बन गया है। चीन और रूस द्वारा दिए गए उपग्रह समर्थन से ईरान को हवाई श्रेष्ठता मिल गई है जिसके कारण उसे रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर बढ़त हासिल है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि युद्ध किस तरह जारी रखा जाए, ट्रम्प नए विकल्प तलाशने के लिए बेताब हैं। इसके साथ ही वे इससे निकलने के रास्ते भी तलाश रहे हैं। मध्यस्थों के माध यम से ईरान से बातचीत करने और जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई की मांग करने वाले उनके बयानों ने उन्हें अस्थिर और अपने ही बयानों का विरोधी दिखाया है।

भारत के अंतिम छोर पर स्थित स्वास्थ्य एवं कल्याण इकोसिस्टम को मजबूत बनाना

प्रतापराव जाधव

अब जबकि भारत सभी के लिए न्यायसंगत, समावेशी और समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमें एक मौलिक प्रश्न पूछना होगारू हम अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक सही समय पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचना कैसे सुनिश्चित करें? इसका जवाब केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार या उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग में ही नहीं, बल्कि उन प्रणालियों को मजबूत करने में भी निहित है जो स्वाभाविक रूप से सुलभ, सस्ती और समुदायों के भरोसे पर खरे उतरते हों। इस संदर्भ में, होम्योपैथी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ–साथ एक मौन लेकिन शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर रही है और जमीनी स्तर पर समग्र स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को बदल रही है। हम यह दिखाई दे रहा है कि होम्योपैथी कैसे जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी वाले शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर रही है। इसके प्रभाव का पता केवल व्यापकता से ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरत वाले स्थानों – यानी अंतिम छोर – तक पहुंचने की क्षमता से भी चल रहा है। अब जबकि हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला शविश्व होम्योपैथी दिवसश्च करीब है, यह इस बात पर विचार करने का एक सही मौका है कि यह प्रणाली केवल व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं बल्कि समग्र कल्याण का एक ऐसा मॉडल बनाने में भी योगदान दे रही है जो किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी हो। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी है। 18वीं शताब्दी में सैमुअल हैनिमैन द्वारा विकसित और 19वीं शताब्दी में भारत लाई गई, होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर यानी समान से समान का उपचार के सिद्धांत पर आधारित है। दशकों से एक समग्र और रोगी–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए, यह भारत की बहुआयामी स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई है। जमीनी स्तर पर होम्योपैथी की सबसे बड़ी खूबी इसकी निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने की क्षमता है। कई पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवा टुकड़ों में बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि निरंतर और रिश्तों से सचालित होती है। होम्योपैथी का व्यक्ति–केन्द्रित उपचार का दृष्टिकोण, खासतौर पर पुरानी बीमारियों, बार–बार होने वाले संक्रमणों और जीवनशैली संबंधी विकारों के प्रबंधन के क्रम में चिकित्सक और रोगी के बीच दीर्घकालिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। यह निरंतरता उपचार के प्रति रोगी के समर्पण और समग्र स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों में उल्लेखनीय सुधार करती है। आज भारत में 290 से अधिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हैं। साथ ही, देशभर में चिकित्सकों का एक विशाल नेटवर्क भी उपलब्ध है। फिर भी, होम्योपैथी के असली प्रभावों को संस्थानों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर – झारखंड के जनजातीय जिलों, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश की दूरदराज की बस्तियों में – बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। वहां एक अकेला चिकित्सक भी सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों में बदलाव ला सकता है। होम्योपैथी की प्रमुख खूबियों में से एक इसकी सरलता भी है। दवाइयां किफायती होती हैं, इन्हें लाना–ले जाना आसान होता है और इनके भंडारण के लिए किसी जटिल भंडारण संरचना की जरूरत ही नहीं होती है। कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं और सीमित स्वास्थ्य सेवा कर्मियों वाले इलाकों में, होम्योपैथी की ये विशेषताएं अनमोल हो जाती हैं। जनजातीय समुदायों, जो हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अक्सर बीमारियों का बेमेल बोझ झेलते हैं, के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सांस्कृतिक रूप से भी अनुकूल होना चाहिए। होम्योपैथी का सौम्य और गैर–आक्रामक रवैया पारंपरिक उपचार पद्धतियों के अनुरूप है, जिससे यह अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य और सुलभ हो जाता है। इसी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं साथ जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत, 12,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) स्थापित किए गए हैं, जो सामुदायिक स्तर पर होम्योपैथी सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होम्योपैथी भारत में गैर–संक्रामक रोगों से निपटने में भी योगदान दे रही है।

डिजिटल जनगणना 2027- भारत की प्रशासनिक क्षमता का नया अध्याय

अरुण

डनायकराजनीतिक विश्लेषण सेवा इस जनगणना के सामाजिक प्रभावों के साथ इसके राजनीतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद परिसीमन के तहत जनसंख्या के आध ाार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित होंगी, और दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि इससे उत्तर भारत को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। संसद में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान भी इसी प्रक्रिया के उपरांत लागू होगा। भारत में पांच वर्षों के विलंब के बाद आरम्भ हुई जनगणना 2027 न केवल आकार में विश्व की सबसे बड़ी है, बल्कि तकनीकी ढांचे और सामाजिक–राजनीतिक प्रभावों के कारण भी अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति आधारित गणना को सम्मिलित किया जाना, डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग, स्वयं गणना का विकल्प, परिसीमन व आरक्षण जैसी नीतिगत प्रक्रियाओं पर इसके दूरगामी प्रभावकृये सभी तत्व इस जनगणना को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए रुपए 11,718.24 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिनमें गणनाकर्मियों के मानदेय, प्रशिक्षण, आईटी अवसंरचना और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं। जनगणना 2027 का आयोजन 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार देश के 36 राज्योंध केंद्रशासित प्रदेशों, 7,092 उप–जिलों, 5,128 सांविधिक नगरों (शहरी एवं प्रशासनिक ढांचा युक्त), 4,580 जनगणना नगरों (स्थानीय प्रशासनिक इकाई विहीन) तथा लगभग 6,39,902 ग्रामों में किया जाएगा।भारत में आध ुनिक जनगणना 1881 में पहली बार पूरे देश में समन्वित रूप से संपन्न हुई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना आयोजित की गई। अब, 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल सोलहवीं जनगणना है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें लगभग 30 लाख गणनाकर्मी स्मार्टफोन आधारित मोबाइल ऐप से सीधे डेटा अपलोड करेंगे। यह ऐप हिन्दी–अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है और बिना इंटरनेट के भी दूरदराज क्षेत्रों में कार्य करता है। यद्यपि गणनाकर्मी पूर्ववत् घर–घर जाकर विवरण संकलित करेंगे, इस बार उत्तरदाताओं को स्व–गणना का विकल्प भी दिया गया है। नागरिक ह्यद्ग. ष्द्गठ्ठह्यह्वह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल पर लॉगिन कर स्थान चिन्हित, गृह विवरण भरने और सूचना प्रेषित करने पर एक विशिष्ट स्व–गणना आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे गणनाकार को देने पर अभिलेख में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह सुविधा समय बचाते हुए नागरिकों को अपनी सुविधा अनुसार जानकारी भरने का अवसर देती है।डिजिटल जनगणना भारत की प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को नई दिशा देने वाला कदम है, जो पारदर्शी, त्वरित और नागरिक–केंद्रित शासन व्यवस्था के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालांकि डिजिटल जनगणना की सफलता डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ–साथ गणनाकर्मियों के प्रशिक्षण, डिजिटल दक्षता और जमीनी स्तर की व्यावहारिक चुनौतियों के प्रभावी समाधान पर भी निर्भर करेगी। जनगणना दो चरणों में संपन्न होगीकृ पहले चरण में गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राज्यों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में की जायेगी। इस चरण में भवन की पहचान, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, निवासियों की संख्या, जल–स्वच्छता–विद्युत–ईंधन की उपलब्धता, घरेलू परिसंपत्तियों तथा परिवार प्रमुख, लिंग और दांपत्य स्थिति जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों सहित कुल 33 प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिनमें सहजीवन को भी स्थिर संबंध मानकर विवाहित की श्रेणी में रखा जाएगा।फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से आयु, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवासन, प्रजनन, धर्म, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तथा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे व्यक्ति–स्तरीय विवरण संकलित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मकान सूचीकरण जनगणना 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि स्व–गणना की अवध‍ि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक रहेगी। 1931 के बाद पहली बार द्वितीय चरण में जाति आधारित गणना की जाएगी, जो इस जनगणना का सबसे चर्चित और विवादास्पद पहलू है, विशेषकर क्योंकि भाजपा प्रारंभ में इसके विरोध में थी। 1951 में श्सामाजिक विभाजनश की आशंका के कारण इसे बंद कर दिया गया था और तब से केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित सीमित जानकारी ही एकत्र होती रही। किंतु वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने इस प्रश्न को पुनरू केंद्र में ला दिया हैय विस्तृत जाति आंकड़ों के अभाव में नीति निर्माण श्अंधेरे में तीर चलानेश्च जैसा हो गया है, जिससे न संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो पा रहा है और न ही वंचित समुदायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो रही है। दूसरी ओर, विरोधियों का तर्क है कि जाति गणना से जातीय पहचानें कठोर होंगी, सामाजिक विभाजन गहरे होंगे और जाति को एक स्थायी सरकारी मान्यता मिल जाएगी। यह बहस केवल शैक्षणिक नहीं हैय इसका सीधा प्रभाव आरक्षण नीति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण जैसे मुद्दों पर पड़ेगा।इस जनगणना के सामाजिक प्रभावों के साथ इसके राजनीतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद परिसीमन के तहत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनर्निर्धारित होंगी,।

लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सड़क हादसे में कार सवार गंभीर घायल

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर सोमवार को रुदौली कोतवाली क्षेत्र में लोहियापुर स्थित श्री कृष्णा ढाबा के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया।अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रही एक कार पीछे से ट्राला में जा घुसी, जिससे कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में भिडंत ट्राला और कार के बीच हुई। सड़क हादसे की सूचना पाते ही सुजागंज चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह व भेलसर चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली भिजवाया। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यातायात बाधित न हो।

अंबेडकर जयंती पर बीबीएयू में चार दिन होंगे खास आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में 11 से 14 अप्रैल के दौरान डॉ. अंबेडकर जयंती और विश्वविद्यालय स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार को प्रेसवार्ता के जरिये कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने बताया कि इन चार दिनों में राष्ट्रीय संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होंगी। बीबीएयू एआई सेंटर, स्किल कोर्स और इनक्यूबेशन सेंटर के जरिये छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है। कार्यक्रम में देश के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर संगोष्ठी में पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. संजय पासवान मुख्य अतिथि रहेंगे। 12 अप्रैल को प्रो. सतीश चंद्र द्विवेदी मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और 14 अप्रैल को राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम कार्यक्रम में शामिल होंगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. केएल महावर ने बताया कि इस दौरान वाद–विवाद, निबंध और रंगोली प्रतियोगिताएं भी होंगी।

एकीकृत व्यवस्था से शिक्षा में बढ़ेगी पारदर्शिता व गुणवत्ता– प्रो. सैनी

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को विकसित भारत के लिए उच्च शिक्षा विषय पर संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम चार सत्रों में हुआ। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि नए विधेयक के तहत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह एक एकीकृत व्यवस्था बनेगी। इससे पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। विशिष्ट अतिथि एनबीआरआई के निदेशक डॉ. अजीत कुमार शासनी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया। मुख्य वक्ता प्रो. राज शरण शाही रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अशोक मोरल ने की। संगोष्ठी में बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा व सीतापुर से आए प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रो. वंदना सहगल, अभाविप के प्रांत संगठन मंत्री अंशुल विद्यार्थी, प्रो. भुवनेश्वरी भारद्वाज, प्रो. शशि भूषण, घनश्याम शाही, प्रो. नीतू सिंह, प्रो. मंजुला उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद रहे।

नाटक संग्रह 'कांच पर चलते लोग' का विमोचन

लखनऊ, (संवाददाता)। रूबरू फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सभागार में इरशाद राही के नाटक संग्रह 'कांच पर चलते लोग' का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी ने की और मुख्य अतिथि जूही कुदुसी रहीं। डॉ. रस्तोगी ने कहा कि पुस्तक की संवेदनात्मक गहराई समाज से जुड़ाव को प्रेरित करती है। जूही कुदुसी ने नाटक संग्रह के अनदेखे यथार्थों को सामने लाने वाली कृति बताया। वरिष्ठ रंगकर्मी सुशील कुमार सिंह ने पुस्तक को रंगमंच और साहित्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु करार दिया। इस दौरान पुस्तक के अंश पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सूफियाना समूह नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही पांच शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को डिजिटल युग है।

शीतगृहों के सुरक्षित संचालन पर जोर, वैज्ञानिक भंडारण से किसानों को होगा लाभ - दिनेश प्रताप सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान निदेशालय, लखनऊ में आयोजित "शीतगृहों की सुदृढ़ता एवं संचालन" विषयक एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान शीतगृहों में आलू भंडारण, भंडारण उपरांत प्रबंधन, मशीनरी सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में शीतगृहों का सुरक्षित और वैज्ञानिक संचालन अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसानों की उपज को सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों और शीतगृह संचालकों को निर्देश दिए कि भंडारण व्यवस्था में निर्धारित सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा समय–समय पर नियमित निरीक्षण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं।मंत्री ने कहा कि पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए शीतगृहों में गैस प्रबंधन, वेंटिलेशन सिस्टम और मशीनरी की नियमित जांच को अनिवार्य बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि भंडारण व्यवस्था अधिक सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय बन सके। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण करने से किसानों की फसलों की गुणवत्ता बनी रहती है और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है।कार्यशाला के दौरान अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, जहां देश के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक आलू उत्पादित होता है।

प्रदेश में आयुष सेवाओं का तेजी से विस्तार, 3950 चिकित्सालयों के माध्यम से मिल रहा लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने और जनसामान्य तक प्राकृतिक एवं पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं, जिनका विकास भारत के ऋषि–मुनियों द्वारा वर्षों के अनुसंधान और अनुभव के आधार पर किया गया है। इन पद्धतियों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों एवं वेदों, विशेषकर अथर्ववेद में मिलता है, जिससे इनकी प्राचीनता और वैज्ञानिक आधार का संकेत मिलता है।।

दो बाइकों की आमने–सामने टक्कर में वृद्ध की मौत, दो युवक घायल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के खेतासराय थाना क्षेत्र के दीदारगंज–खेतासराय मार्ग पर अब्बोपुर गांव के पास रविवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने–सामने भिड़ंत में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अब्बोपुर निवासी बिहारी बिंद (60) अपनी मोटरसाइकिल से घर से मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खेतासराय की तरफ से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बिहारी बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक पर सवार आजमगढ़ जनपद के अरनौला निवासी सागर (25) और सनी राजभर (23) भी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहारी बिंद की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का इलाज जारी है।

बिहार में जहरीली शराब कांड का कनेक्शन जौनपुर से, आरोपी की तलाश में बिहार पुलिस की छापेमारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले की जांच अब जौनपुर तक पहुंच गई है। इस मामले में एक संदिग्ध आरोपी की तलाश में बिहार पुलिस ने रविवार रात जौनपुर पुलिस के सहयोग से जलालपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। घटना ने दोनों राज्यों की पुलिस को सतर्क कर दिया है और जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है।जलालपुर थाना क्षेत्र के नहोरा डेरवा गांव निवासी लल्लन सिंह के पुत्र चंदन सिंह का नाम इस मामले में सामने आया है। आरोपी की तलाश में पहुंची बिहार पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। घर पर केवल उसकी मां मौजूद थीं, जिन्हें पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के यहां भी लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार पुलिस की टीम लल्लन सिंह के अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि आरोपी के बारे में अहम सुराग जुटाए जा सकें। स्थानीय पुलिस भी इस पूरे ऑपरेशन में सक्रिय सहयोग दे रही है। इस संबंध में सोमवार को जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जौनपुर आई हुई है और जिले स्तर पर भी तीन पुलिस टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में छापेमारी के बाद यह साफ हो गया है कि इस कांड के तार दूसरे जिलों और राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।

नवंबर तक विभागीय बजट का शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें राकेश सचान

लखनऊ, (संवाददाता)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने वित्तीय वर्ष 2026–27 की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय बजट का शत–प्रतिशत उपयोग नवंबर 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर ही प्रदेश में एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान की जा सकती है।शुक्रवार को डालीबाग स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भवन, लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि जिन विभागीय सेक्शनों की कार्ययोजनाएं अभी तक शासन को नहीं भेजी गई हैं, उन्हें बिना विलंब तत्काल प्रेषित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन प्रस्तावों पर अभी तक कार्यवाही लंबित है, उनकी वित्तीय स्वीकृतियां शीघ्र जारी कराई जाएं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि विभाग से संबंधित अधिकतम कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएं। इसके लिए मंडल–स्तर पर प्रदर्शनियों और जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तृत कैलेंडर तैयार किया जाए तथा समयबद्ध तरीके से इनका आयोजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सके।मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को सभी योजनाओं के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय करने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति की सतत समीक्षा से ही लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय उत्पादों को बाजार में बेहतर पहचान मिल सकेगी।बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की और आगामी कार्ययोजना का विस्तृत खाका रखा। मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर योजनाओं को पूरा करने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रदेश में ट्रांसफार्मर मरम्मत से तीन अरब की बचत, अभियंताओं से वसूली आदेश पर बढ़ा विरोध

लखनऊ, (संवाददाता)। ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने की दर में करीब चार फीसदी की गिरावट आई है। निगरानी बढ़ाने के साथ ही वर्ष में दो बार अनुरक्षण कार्य करने के कारण ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इससे प्रत्येक वर्ष करीब तीन अरब से ज्यादा की बचत होने का अनुमान है। अब पॉवर कॉर्पोरेशन ट्रांसफार्मरों की क्षतिग्रस्तता दर को और कम करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष करीब 25 से 30 लाख वितरण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं। इसी तरह करीब 150 से 200 वितरण ट्रांसफार्मर जलते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता कम करने के लिए नई रणनीति अपनाई। इसके तहत वर्ष में दो अनुरक्षण माह घोषित किए गए। इसमें प्रत्येक ट्रांसफार्मर की जांच, तेल डालने की प्रक्रिया सहित अन्य गतिविधियां चलाई गईं। इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक जलने वाले ट्रांसफार्मरों की संख्या के अनुसार अवर अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता और निदेशक स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई थी। इसमें कारण बताओ नोटिस, निलंबन जैसी कार्रवाई शामिल थी। इस वर्ष पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता को कम से कम करने के लिए अभियंताओं से वसूली का आदेश दे दिया। इसके तहत 10 से 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के जलने पर अवर अभियंता से 50, एसडीओ से 30, अधिशासी अभियंता से 20 फीसदी कीमत वसूली जाएगी। इसी तरह 100 से 250 केवीए के ट्रांसफार्मर के जलने पर अवर अभियंता से 40, एसडीओ से 40 और अधिशासी से 20 फीसदी कीमत वसूली जाएगी। इस आदेश को लेकर अभियंता विरोध कर रहे हैं। अभियंताओं का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने के कई कारण हैं। ओवरलोड से लेकर रखरखाव में लापरवाही के साथ ही अर्थिंग की जांच न होना, ट्रांसफार्मर में तेल न डालना, मरम्मत में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग करने से भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं। अध्यक्ष यूपी पावर कार्पोरेशन डा. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि अनुरक्षण कार्य कराने, अर्थिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने, नियमित तेल डालने, फ्यूज सेट, टेललेस यूनिट, ओवर लोडिंग रोकने आदि की व्यवस्था करने की वजह से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता में कमी आई है। नया आदेश अभियंताओं को जिम्मेदारी का अहसास कराने के लिए किया गया है। हमारी कोशिश है कि एक भी ट्रांसफार्मर जलने न पाए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की नई दिशा में भाजपा का ऐतिहासिक कदम : सीमा द्विवेदी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,13 अप्रैल । यूपी के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों को लेकर सोमवार को डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की आधी आबादी को राजनीतिक मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने का मजबूत माध्यम बनेगा। सीमा द्विवेदी ने बताया कि संसद के 16 से 18 अप्रैल तक प्रस्तावित विशेष सत्र में अधिनियम से जुड़ी तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की योजना है, जिससे महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने पर मंथन चल रहा है, ताकि वर्ष 2029 के चुनावों में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'महिला विकास' से आगे बढ़कर 'महिला नेतृत्व वाले विकास' की दिशा में अग्रसर है। यह अधिनियम केवल कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और भागीदारी का प्रतीक है। कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया गया कि 14 अप्रैल को बूथ स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम, 15–16 अप्रैल को 'शक्ति वंदन' पदयात्रा और 18 अप्रैल को विशेष सत्र के उपलक्ष्य में विजय उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत जिले में 'नारी शक्ति पदयात्रा' और स्कूटी रैलियों का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर टीडी कॉलेज की प्रिंसिपल अर्चना सिंह ने मातृशक्ति से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। उन्होंने विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे देश के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगा।

समाज सुधारक और संविधान के शिल्पी थे बाबा साहेब : डॉ. रमेश यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओ का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न विभागों एवं संख्या के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर रज्जू भैया संस्थान में पोस्टर प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में छात्र–छात्राओं ने भाग लिया और डॉ. अंबेडकर के जीवन, विचारों एवं उनके सामाजिक योगदान को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को डॉ अम्बेडकर की जन्मजयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता विधि संकाय, टी डी कॉलेज के रमेश चंद्र यादव ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनका जीवन दर्शन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष करते हुए दलितों, वंचितों और कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने का कार्य किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि डॉ अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना। श्रमिकों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके विचार आज भी एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। सभी कार्यक्रमों का संचालन डॉ नितेश जायसवाल ने किया। इस अवसर पर डॉ जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ सुनील कुमार, डॉ सुशील कुमार, डॉ रामांशु सिंह, सौरभ सिंह, डॉ दिनेश सिंह, डॉ मंगला यादव व बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे।

जौनपुर में प्लाटून पुल का लोकार्पण, शहरी क्षेत्र को जाम से मिलेगी राहत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में शहरी क्षेत्र की जनता को जाम की समस्या से राहत देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बदलापुर पड़ाव से तूतीपुर तक गोमती नदी पर बने प्लाटून पुल (पीपे का पुल) को रविवार को जनता को समर्पित कर दिया गया। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने विधिवत पूजन–अर्चन के साथ पुल का लोकार्पण किया। लगभग 66.75 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद के शहरी क्षेत्र के बीचों–बीच बहने वाली गोमती नदी के कारण शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक बड़ी आबादी नदी के इस पार तो दूसरी उस पार रहती है। आवागमन के लिए सीमित पक्के पुल होने के कारण जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले सिपाह अचला देवी घाट से मियांपुर तक एक प्लाटून पुल बनाया गया था, जो पहले से ही जनता के उपयोग में है। वहीं अब बदलापुर पड़ाव से तूतीपुर तक बने इस नए पुल के शुरू होने से कटघरा, ताड़तला, मखदूम शाह अढ़न, अबीरगढ़ टोला, तूतीपुर, पानदरीबा और पुरानी बाजार समेत कई मोहल्लों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गिरीश चंद्र यादव ने यह भी कहा कि शास्त्री पुल के समानांतर एक नए पक्के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें हो रही देरी को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और अब निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव मिश्रा, नगर अध्यक्ष कमलेश निषाद, जिला महामंत्री अजय सिंह, मनीष श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंघानिया, सभासद नंदलाल यादव, विष्णु सेठ, सिपिन सिंह,मुन्ना सिंह, ब्रह्रोश शुक्ला,अभिषेक श्रीवास्तव, दीपू मिश्र सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आयुष मंत्री की अपील केमिकल व साइड इफेक्ट मुक्त इलाज से जुड़ें लोग

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्रा दयालु ने लोगों से केमिकल और साइड इफेक्ट मुक्त उपचार पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में सुरक्षित, असरदार और प्राकृतिक इलाज की बढ़ती मांग के बीच होम्योपैथी एक भरोसेमंद और प्रभावी विकल्प बनकर तेजी से उभर रही है।विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में आयुष मंत्री ने होम्योपैथी की उपयोगिता और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी केवल एक उपचार पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह शरीर की आंतरिक रोग–प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत समान को ठीक करता है यानी जैसा रोग होता है, उसी प्रकार की औषधि से उसका उपचार किया जाता है, जिससे रोग को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है। डॉ दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि वर्तमान समय में जब लोग साइड इफेक्ट से मुक्त और केमिकल रहित उपचार की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में होम्योपैथी एक सुरक्षित, सरल और किफायती विकल्प के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पद्धति न केवल रोगों के उपचार में सहायक है, बल्कि यह शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता को भी मजबूत बनाती है, जिससे व्यक्ति दीर्घकाल तक स्वस्थ रह सकता है।उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और प्राकृतिक जीवनशैली को अपनाने के साथ इस पद्धति से जुड़कर स्वस्थ समाज के निर्माण ।

जनसुनवाई के दौरान महिला एसओ तथा उनकी टीम मौके पर फरियादियों की समस्या की कर रही समाधान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ) अयोध्या।एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेस 5 नोडल प्रभारी बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी की पर्यवेक्षण में प्रतिदिन महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला जहां एक ओर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को स्कूलों, चौराहा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर अपनी टीम के साथ जाकर महिलाओं बालिकाओं तथा छात्रों को जागरुक कर रही हैं।वहीं महिला थाना पर आने वाली दूर दराज से फरियादियों की समस्याओं का समाधान जनसुनवाई के दौरान अपनी सूझबूझ से भी कर रही हैं।जनसुनवाई के दौरान पति–पत्नी से मनमुटाव,छोटी–छोटी बातों में पति–पत्नी के बीच वाद विवाद उत्पन्न होना सहित कई जटिल समस्याओं का समाधान हुए कुछ ही समय में निपटारा कर रहे है।उनके साथ–साथ इन फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने में महिला थाना पर तैनात महिला उप निरीक्षक सोनी सिंह, चेतना पांडेय, श्वेता राठौड़, प्रिया भी सहयोग करते हुए दिखाई दे रही थी।

लखनऊ में स्वर्णकार समाज का ऐतिहासिक सोनार- समागम. जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और देश से 10000 से ज्यादा की संख्या में उमड़ा सुनारों का जन सैलाब

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय सभागार चारबाग में कल स्वर्णकार समाज की एकजुटता का एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला. समाज को संगठित करने और आजादी के 78 वर्षों बाद भी राजनीति के क्षेत्र में स्वर्णकार समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व ना मिलने की पीड़ा लेकर,स्वर्णकार समाज की सुरक्षा,स्वर्णकार समाज को हर दल में राजनीतिक भागीदारी की मांग को लेकर ऐतिहासिक महाकुंभ का सैलाब दिखाई दिया. इस विशाल सोनार–समागम का सफल आयोजन मुख्य आयोजक मनीष कुमार वर्मा तथा राजेश सोनी, कमलेश सोनी, बन्नू भैया, आकाश वर्मा, पंकज वर्मा आदि के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत बिहार से आए अशोक वर्मा जी के हाथों दीप जलाकर तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पी. एल. सोनी के द्वारा की गई।

कार्यक्रम का संचालन अनुराग वर्मा तथा सुषमा सोनी के द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के आयोजक मनीष कुमार वर्मा जी तथा राजेश सोनी ने अपने उद्बोधन मे सभी दलों से स्वर्णकार समाज को उचित प्रतिनिधित्व की मांग की. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार समाज को उचित प्रतिनिधि नहीं मिला तो सरकार समाज भी अपने दल की स्थापना करने को मजबूर हो जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव से पहले स्वर्णकार समाज की अपनी मांगो को लेकर देश व प्रदेश के सभी स्वर्णकार समाज की 1 लाख से ज्यादा की रैली की जाएगी।

अंत में कार्यक्रम के आयोजक मनीष कुमार वर्मा, राजेश सोनी, कमलेश रस्तोगी तथा कार्यक्रम संचालक अनुराग वर्मा, सुषमा सोनी, ने दूर–दूर से आए सभी सरकार बांधों का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम को विशाल बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया।

सहायक अध्यापक इंजीनियर अंकित तिवारी ने समीक्षा अधिकारी व सौरभ पांडे ने आयकर विभाग में चयनित होकर माता–पिता का किया नाम रोशन

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ) अयोध्या।कुछ दिन पूर्व जारी हुए यूपीएससी परीक्षा परिणाम में उत्तर प्रदेश में 38वीं रैंक हासिल करने वाले सहायक अध्यापक इंजीनियर अंकित कुमार तिवारी आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया।पर अभी उनके द्वारा उससे भी आगे बढ़ने का सपना है।बताते चले कि इं.अंकित कुमार तिवारी बीकापुर विकास खंड ग्राम पंचायत पुहुंपी के मजरे पूरे देश तिवारी का पुरवा के निवासी है।उनके पिता ओंम प्रकाश तिवारी किसान और बीमा अभिकर्ता है।वर्ष 2017 में केंद्रीय विद्यालय बलिया, में उन्होंने पहली नौकरी की प्राप्त किया उसके वर्ष 2018 में बेसिक शिक्षा विभाग में, तारुन ब्लाक क्षेत्र में अपनी सेवा दिया वर्ष 2022 में शादी होने के बाद पत्नी भी शिक्षिका थी इसलिए उन्होंने 2026 में उन्होंने मैनुअल ट्रांसफर लिया और पति पत्नी दोनों एक साथ मिल्कीपुर ब्लाक क्षेत्र ड्यूटी करने लगे।लेकिन उनके मन में सपना चल रहा था जिसकी तैयारी वह करते रहे।आखिरकार उन्होंने इस सफलता को हासिल कर लिया।और समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर चयन हुआ।जिसको लेकर गांव शिक्षा विभाग और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई।इसी दौरान एक वर्ष पहले दिल को हिला देने वाली घटना भी घटी जिसमें इंजीनियर अंकित कुमार तिवारी ने की माता का निधन हो गया।पर ऐसी घटना के बाद अंकित और उनकी पत्नी एक ही विभाग में रहकर पत्नी का भरपूर सहयोग मिलने पर इं अंकित कुमार तिवारी ने इस सफलता को हासिल कर लिया।अपनी कठिन मेहनत के बल पर इस कठिन परीक्षा की लाइन को चीरते हुए उत्तर प्रदेश में 38वें रैंक पर सफलता हासिल किया।उसी क्रम में रविवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित होकर सम्मानित किया।इसी कड़ी में भाजपा नेता शैलेंद्र पांडेय मोनू, अजय पांडेय, अशोक तिवारी, रंजीत तिवारी, दीपक पांडेय, संतोष मिश्रा, हर्षित पांडेय, विवेक सिंह, राम गोपाल पांडेय, योगेश त्रिपाठी, आदित्य पांडेय, इं. अमित पांडेय, कथा वाचक पंडित केशरी प्रसाद शुक्ला, राम चरन निषाद कोटेदार, शिक्षक राज कुमार यादव, गया प्रसाद यादव, अरविंद तिवारी, आदर्श जी तिवारी, देवमणि तिवारी, फूलचंद यादव, जय प्रकाश तिवारी, अंकित के पिता ओम प्रकाश तिवारी, भाई विवेक तिवारी, भूपेंद्र तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, भरतजी श्रीवास्तव, विवेक तिवारी मोनू सहित सैंकड़ों की संख्या में लोगों ने अंग वस्त्र देकर माला पहना कर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया।

वहीं दूसरी तरफ भी खुशी का माहौल रहा महज 20 वर्ष के सौरभ पाण्डेय पुत्र दीपक पांडेय निवासी ग्राम जेरुआ ने भी अपनी कठिन परिश्रम के बल पर आफिस सुप्रीम टंडन आयकर विभाग भारत सरकार की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए 3380 वीं रैंक हासिल किया है।इं.अंकित कुमार तिवारी के भांजे भी है।सौरभ पाण्डेय के पिता घर पर रहकर खेती किसानी का कार्य करते हैं। इस खुशी के अवसर पर दोनों सफलता हासिल किए यूवकों का सम्मान किया गया।

एनसीसी अयोध्या सूबेदार ने किया श्री राम वल्लभा भगवंत विद्यापीठ इंटर कॉलेज का निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर) अयोध्या।सोमवार को श्री राम वल्लभा भगवंत विद्यापीठ इंटर कॉलेज ड्योढ़ी अयोध्या में संचालित एनसीसी का निरीक्षण 65 बटालियन एनसीसी अयोध्या के सूबेदार मेजर बहादुर सिंह के नेतृत्व में किया गया।निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यापीठ में एनसीसी गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना था।बटालियन के निर्देशानुसार एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संबंधित एनसीसी इकाइयों में किया जाना अनिवार्य है।इसी के दृष्टिगत आज एनसीसी बटालियन के अधिकारियों के द्वारा विद्यालय का एवं उससे संबंधित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास एवं डिग्री कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के उपरांत प्रशिक्षण शिविर के जरूरत हेतु कुछ आवश्यक सुझाव विद्यापीठ के प्रधानाचार्य को सूबेदार मेजर बहादुर सिंह जी के द्वारा दिया गया।इस अवसर पर जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ आलोक तिवारी जी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर को सकुशल संचालित करने के लिए अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया।इस अवसर पर सीटीओ श्री आकाश गौर जी, लेफ्टिनेंट राकेश मौर्य, सूबेदार प्रभाकर सिंह एवं अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।

महिला एसओ आशा शुक्ला ने महिला एसआई श्वेता राठौड़ व चेतना पाडे के साथ मिशन शक्तिअभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया जागरुक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ) अयोध्या। सोमवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ ने कांस्टेबल प्रिया सिंह, महिला पीआरडी माधुरी तथा साधना सिंह व महिला होमगार्ड शोभा के साथ शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह चौक,कैंट रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न चौराहा तथा सार्वजनिक स्थानों पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरुक किया।इसी कड़ी में महिला उप निरीक्षक चेतना पांडे ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, रिकाबगंज, बल्लाहाता,चौक रोडवेज सहित अन्य प्रमुख चौराहा तथा मार्गों पर महिलाओं व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उनके साथ मौजूद रही महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर ने बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

कुर्सी रोड महायोजना को लेकर केन्द्रीय रक्षामंत्री से मिलेंगे व्यापारी

महायोजना के पुर्नविचार को लेकर एकजुट हुये व्यापारी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ। कुर्सी रोड के व्यापारियों, उद्यमियों, शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों एवं भवन स्वामियों ने आज यहां बैठक कर कुर्सी रोड महायोजना–2031 के पुर्नविचार की मांग को लेकर केन्द्रीय रक्षामंत्री व शहर के सांसद श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। इसके लिये मुलाकात करने के लिये अतिशीघ्र प्रतिनिधि मण्डल का गठन किया जायेगा। आज यहां कुर्सी रोड स्थित एसएस ग्रैण्ड होटल में हुयी बैठक में अंजनी कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, ऋषि त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा कमलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रमिक जनशक्ति किसान यूनियन, , चन्द्रमौलि शुक्ला, पंकज तिवारी, अध्यक्ष जनविकास महासभा सहित उद्यमियों आराधना कुमार, मोहम्मद सलीम सहित काफी संख्या व्यापारी, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि व भवन स्वामी मौजूद थे। बैठक में कुर्सीरोड महायोजना–2031 को हजारों लोगों की रोजी–रोटी छिनने वाला बताते हुये कहा गया कि इस महायोजना–2031 को हर हाल में रोकने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगें और इसके लिये व्यापारियों व उद्यमियों का एक प्रतिनिधि मण्डल लखनऊ या दिल्ली स्थित आवास पर केन्द्रीय रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात इस मामले हस्तक्षेप की मांग करेंगे। मालूम हो कि इस महायोजना के अन्तर्गत कुर्सी रोड के चौड़ीकरण के अन्तर्गत टेढ़ी पुलिया से सिकन्दरपुर चौराहे तक 45 मीटर, सिकन्दरपुर चौराहे से कॉरपोरेशन बैंक, मिश्रपुर तक 80 मीटर और कॉरपोरेशन बैंक से बसहा तक 150 मीटर तथा बसहा से बेहटा तक 100 मीटर रोड चौड़ी करने का प्रस्ताव है, जिसके लागू होने से हजारों व्यापारी, गृह स्वामी, मल्टी स्टोरी, होटल, छात्रावास, धार्मिक स्थल पूर्णतः ध्वस्त होने की कगार पर है, जिससे लोगों की न सिर्फ पूरे जीवन की कमाई दांव पर लगी है बल्कि हजारों परिवारों के सामने जीवनयापन पर संकट खड़ा हो जाएगा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने कहा पूर्व में भी व्यापारियों की समस्याओं को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक व प्रमुख सचिव ग्रह को लिखित में अवगत कराया जा चुका है।

डीडीयू : बीए में 30 और एमए में 25 प्रतिशत सीट वृद्धि

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में आयोजित विभागाध्यक्षों की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया। बढ़ी सीटों पर प्रवेश स्ववित्तपोषित माध्यम से दिया जाएगा। अब इसे मंजूरी के लिए प्रवेश समिति में ले जाने की तैयारी है। निर्णय के अनुसार, बीए में सेल्फ फाइनेंस मोड में 30 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह एमए के सभी विषयों में 25 प्रतिशत की सीट वृद्धि हुई है। बीएससी, एमएससी और एमकॉम के नियमित पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीट वृद्धि सत्र 2026–27 में लागू होगी। सीट वृद्धि को लेकर बृहस्पतिवार को भी अधिष्ठाताओं के साथ कुलपति ने बैठक की थी। उसमें सीट वृद्धि पर सहमति बन गई थी। शुक्रवार को इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया। डीडीयू में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू होनी है। इसे लेकर इस निर्णय को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रवेश के लिए ज्यादातर छात्रों की पहली पसंद विश्वविद्यालय परिसर ही होता है। इसीलिए हर वर्ष स्नातक और परास्नातक में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। उनमें से करीब 12–15 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल पाता है। सीट वृद्धि होने पर संबंधित पाठ्यक्रमों में छात्रों के अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इन विषयों में 60–60 सीटों पर लिया जाएगा प्रवेश परास्नातक में स्ववित्तपोषित माध्यमों से संचालित एमएससी के कई विषयों में 60–60 सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सीएम डैश बोर्ड में चमका भदोही, मिला 11वां स्थान

भदोही, (संवाददाता)। भदोही ने विकास कार्यों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मार्च में सीएम डैशबोर्ड (विकास कार्य) में प्रदेश स्तर पर 11वां स्थान प्राप्त किया है, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। जनवरी 2026 में 15वीं एवं फरवरी 2026 में 16वां स्थान मिला था। विभागों के सहयोग से पांच अंकों का सुधार हुआ है। डीएम शैलेष कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन विभागाध्यक्षों की ओर से किया गया है। बताया कि जिले की प्रगति 96.40 प्रतिशत दर्ज की गई है, इसमें 72 इंडिकेटरध्योजनाओं में ए ग्रेड, पांच इंडिकेटर में बी ग्रेड प्राप्त करते हुए बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, कृषि, सामाजिक कल्याण एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

पूराकलन्दर पुलिस ने 5.5 लाख रुपये की ठगी के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर) अयोध्या।थाना पूराकलन्दर पुलिस ने 5.5 लाख रुपये की ठगी के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कूटरचित आधार कार्ड बनाकर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की।पीड़िता से मकान बनवाने हेतु जमीन दिखाकर ₹5,50,000 हड़प लिए गए।पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी और गाली–गलौज की।इस मामले में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 84ध्26 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मामले में कई धाराएं बढ़ाई गईं, जिनमें धोखाधड़ी, धमकी और अन्य अपराध शामिल हैं। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान संजय वर्मा और अंकित यादव को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया।तीसरे आरोपी अनिकेत यादव को देर रात मसौधा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।मुख्य आरोपी संजय वर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट व एनडीपीएस जैसे मामले शामिल हैं।

नगर के नामित दस नामित पार्षदों को महापौर ने दिलाई शपथ

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता) अयोध्या। नगर निगम के नामित दस पार्षदों को सर्किट हाउस में समारोह पूर्वक शपथ दिलाई गई इसी के साथ पार्षदों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है।सोमवार को आयोजित समारोह में विधायक वेदप्रकाश गुप्ता एवं शहर के संभ्रांतजन एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने सभी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ ही उम्मीद जताई

कि नगर निगम को बेहतर ढंग से संचालन में नामित पार्षद अब निर्वाचित पार्षदों के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। विकास की डगर पर अयोध्या को और तेजी से आगे ले जाने में योगदान देंगे। नामित पार्षदों में सुशील मिश्र बबलू, संजय निषाद, लक्ष्मण वर्मा, संजय कोरी, सुशील कुमार सिंह, रंजना सागर, आशुतोष पांडेय, ज्ञान केसरवानी, सुनीता गुप्ता एवं अर्चना द्विवेदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन सहायक नगर आयुक्त गुरुप्रसाद पांडे ने किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, नगर निगम के उपसभापति संतोष सिंह, निवृतमान उपसभापति राजेश गौड़, प्रकाश गुप्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे कुन्नू मनोज जायसवाल रंजीत शर्मा आदि मौजूद रहे।

आधा दर्जन विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान रैली और गोष्ठी संपन्न

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ) अयोध्या। दिशा संस्था ब्लॉक मसौधा के तत्वाधान में मसौधा ब्लॉक के अंतर्गत छः प्राइमरी एवं कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान और गोष्ठी का आयोजन किया गया।बताते चलें कि शनिवार को कंपोजिट विद्यालय धर्मदासपुर में खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि स्वास्थ्य अमिताभ सिंह के साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिशा संस्था राजाराम जी द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया साथ ही साथ नंदीग्राम भदरसा भरत कुण्ड में भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल सोमवार को प्राइमरी स्कूल जमुरतगंज पूरा कलंदर नोडल टीचर ज्योति यादव आंगनवाड़ी वंदना वर्मा द्वारा सहयोग किया गयाऔर कंपोजिट विद्यालय अरुवावाँ में नोडल टीचर निशा सिंह सहायक टीचर अजीज मेंहदी आंगनबाड़ी दयावती द्वारा सहयोग किया गया तत्पश्चात प्राइमरी स्कूल कल्याण मदरसा पगला भारी में नोडल टीचर रश्मि जायसवाल सहायक टीचर शिखा यादव और सोनी कुमारी प्राइमरी स्कूल जीवपुर रामा पाण्डेय और अन्य सहायक टीचरों के द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली का और गोष्ठी का आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. बच्चों द्वारा प्रेरक नारे लगाए गए जिनमें मुख्य रूप से आधी रोटी खाएंगे स्कूल रोज जाएंगे पढ़ी–लिखी लड़की घर की रोशनी लगाए गए।ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजाराम जी द्वारा और सुगम कर्ता मीरा देवी और रीता द्वारा बच्चों को स्कूल प्रतिदिन जाने के लिए प्रेरित किया गया एक भी दिन स्कूल से अनुपस्थित नहीं होना चाहिए।निवर्तमान ब्लाक मोबिलाइजर कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ ब्लॉक मसौधा धीरेंद्र नाथ पाण्डेय बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके अवश्य लगवाने चाहिए।जिनमें टीबी.गला घोंटू.काली खांसी के साथ साथ टेटनेस.पोलियो.पीलिया.निमोनिया. खसरा रूबेला.दिमागी बुखार और दस्त प्रबंधन पर जोर डाला आपके द्वारा रैली और गोष्ठी का संचालन किया गया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।